

पुल ढहने की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने बिहार सरकार से एक [रिट याचिका](#) पर प्रत्युत्तर मांगा है, जो राज्य में बार-बार [पुल ढहने की घटनाओं](#) को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

- [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) ने बिहार में पुलों के उच्चस्तरीय संरचनात्मक ऑडिट के साथ-साथ पूरा रक्षा के लिये कमज़ोर निर्माणों (प्रमुखतः पुल) को इरादतन ध्वस्त करने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिये [दायर की गई याचिका](#) के जवाब में नोटिस जारी किया।
- याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पुलों की वास्तविक समय नगिरानी के लिये एक नीतिया प्रणाली स्थापित करे, जो [राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं](#) के संरक्षण के लिये [सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय](#) द्वारा बकिसति तंत्र के समान हो।
 - उक्त संदर्भित नीतिका फोकस ["सेंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय पर स्थिति नगिरानी की पहचान और कार्यान्वयन"](#) पर होना चाहिये।